

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1413-दो/2017 विरुद्ध आदेश दिनांक  
17-5-2017- पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर,  
जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 01 अ-68/2016-17

1- लाखन सिंह पुत्र कल्याण सिंह

2- कृष्णभान पुत्र लाखन सिंह

ग्राम पठारी तहसील अशोकनगर

जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री आर.पी.पालीवाल)

आ दे श

(आज दिनांक १ - ३ - 2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक  
01 अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-5-2017 के विरुद्ध  
म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का सारोँश यह है कि पठवारी हलका नंबर 36 ने इस आशय की  
रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आवेदकगण ने ग्राम पठारी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक  
194 रकबा 0.042 हैक्टर पर अतिक्रमण कर लिया है। पठवारी रिपोर्ट पर से नायव  
तहसीलदार वृत्त राजपुर तहसील अशोकनगर ने प्रकरण पेंजीबद्ध किया तथा  
आवेदकगण को सुनवाई के लिये आहुत किया। आवेदकगण ने अभिभाषक के माध्यम  
से उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया। आवेदकगण द्वारा नायव तहसीलदार के समक्ष

व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके क्रम में नायब तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 12-7-16 से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित कर अग्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 01 अ-68/2016-17 पंजीबद्ध करके आवेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये आदेश दिनांक 17-5-17 पारित किया तथा आवेदकगण का शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना प्रमाणित पाने के आधार पर एवं कब्जा न छोड़ने से गिरफ्तारी वारन्ट जारी करना आदेशित किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभ पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।


4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 01 अ-68/2016-17 में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि पटवारी द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आवेदकगण के विरुद्ध नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई का अवसर देने हेतु आहुत किया है जिसमें आवेदकगण की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया है। नायब तहसीलदार ने जाँच में अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित पाया तथा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर प्रतिवेदन दिनांक 12-7-16 प्रस्तुत कर इस प्रकार प्रतिवेदित किया है :-

“ मान0 द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के प्र0क0 7/2015 में पारित आदेश दिनांक 10-12-15 की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें सर्वे क्रमांक 198 रकबा 0.031 है. में रास्ता पर अतिक्रमण न करने व कोई निर्माण कार्य न करने का स्थगन आदेश दिया था, परन्तु कल्याण सिंह उस उसके पुत्रों द्वारा स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुये उक्त रास्ता पर टीन शैड डालकर - टपरा बना दिये गये हैं तथा तार फेंसिंग कर पूर्ण रूप से रास्ता बंद कर दिया गया है। अतः स्थगन आदेश के उल्लंघन करने से अनावेदक कल्याण सिंह के विरुद्ध सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर प्रकरण सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर भेजा जावे। ”

अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण प्राप्ति उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 19-12-16 से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सूचना पत्र जारी किया है जिस पर आवेदकगण के अभिभाषक ने उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया है एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेशी 24-12-16,

28-12-16, 10.1.17, 25-1-17, 9-2-17, 22-2-17, 21-3-17, 11-4-17, 27-5-17 तक आवेदकगण को निरन्तर लेखी / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है परन्तु आवेदकगण द्वारा पर्याप्त अवसर मिलने एवं समय रहते सार्वजनिक उपयोग के रास्ते की भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 01 अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-5-2017 से आवेदकगण के विरुद्ध सिविल जेल की कार्यवाही की है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्र0क0 01 अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-5-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।



(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल,  
मध्य प्रदेश ग्वालियर